वर्ष 18
अंक 251
10 पृष्ठ
मूल्य 5 रुपये

मंगलवार, 9 दिसंबर 2025

कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, **नई दिल्ली**, भोपाल, मुंबई और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार www.bshindi.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड

पृष्ठ 2

यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 20 फीसदी बढ़ी

नरेंद्र मोदी पृष्ठ 10

‘वंदे मातरम को कांग्रेस ने छोटा किया’

डॉलर रु. 90.10 ▲ 0.10 पैसा | यूरो रु. 104.90 (अपरिवर्तित) | सोना (10 ग्राम) रु. 1,27,743 ▼ 334 रु. | सेंसेक्स 85102.70 ▼ 609.70 | निफ्टी 25960.60 ▼ 225.90 | निफ्टी फ्यूचर्स 26064.70 ▲ 104.10 | ब्रेंट क्रूड 63.20 ▼ 0.80 डॉलर

एक नज़र

सूचकांकों में दो महीने की सबसे बड़ी गिरावट

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की घोषणा से पहले सतर्कता और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर अनिश्चितता के बीच सोमवार को बेंचमार्क सूचकांकों में करीब दो महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 837 अंक तक लुढ़क गया था मगर बाद में थोड़े नुकसान की भरपाई कर 610 अंक की गिरावट के साथ 85,103 पर बंद हुआ। निफ्टी 226 अंक नीचे 25,961 पर बंद हुआ। पृष्ठ 3

आईसीआईसीआई प्रू. का मूल्य दायरा तय

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट मैनेजमेंट कंपनी ने शुक्रवार को खुलने वाले अपने 10,600 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 2,061 रुपये से 2,165 रुपये प्रति शेयर का कीमत दायरा तय किया है। इस दायरे के ऊपरी स्तर पर देश की सबसे बड़ी ऐसेट मैनेजर कंपनी का मूल्यांकन 1.07 लाख करोड़ रुपये होगा। पृष्ठ 3

बीमा क्षेत्र की वृद्धि 20 फीसदी के पार

वित्त वर्ष 2026 में पहली बार नवंबर महीने में बीमा उद्योग के प्रीमियम में 20 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। बीमा प्रीमियम पर माल एवं सेवा कर 18 फीसदी से घटाकर शून्य किए जाने और अनुकूल आधार के असर के कारण ऐसा हुआ है। जीवन बीमा कंपनियों का नवंबर में न्यू बिजनेस प्रीमियम करीब 23 फीसदी बढ़कर 31,119.6 करोड़ रुपये हो गया है जबकि गैर जीवन बीमाकर्ताओं ने सालाना आधार पर 24.17 फीसदी वृद्धि दर्ज की है और यह 26,897.4 करोड़ रुपये हो गया है। पृष्ठ 4

भारत और रूस गैर-शुल्क बाधाएं दूर करेंगे

भारत और रूस समुद्री उत्पाद, डेरी और पोल्ट्री सहित औषधि और कृषि क्षेत्रों में गैर-शुल्क बाधाओं को लेकर भारत की चिंता को दूर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत ने ये मुद्दे रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान उठाए गए थे। इसके बाद इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास तेज हुए। पृष्ठ 4

इंडिगो पर होगी कड़ी कार्रवाई

सीईओ को हटाने के मुद्दे पर विमानन कंपनी का निदेशक मंडल एकमत नहीं

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 8 दिसंबर

इंडिगो की मौजूदा स्थिति पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज कहा कि सरकार ने विमानन कंपनी के परिचालन में हालिया गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी है और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि विमानन क्षेत्र के लिए मिसाल पेश की जा सके। इधर इंडिगो के बोर्ड सदस्य अभी भी इस बात पर पक्के नहीं हैं कि कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स को हटाया जाना चाहिए या नहीं।

इस बीच एल्बर्स और इंडिगो के मुख्य परिचालन अधिकारी इसिड्रो पोरक्वेरास ने देर शाम नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि कंपनी की जटिलता और बड़े पैमाने के परिचालन के कारण इस समय संचालन में रुकावट का सटीक कारण बताना संभव नहीं है।

नायडू ने राज्य सभा में अपने भाषण में इस संकट के लिए सीधे तौर पर इंडिगो को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, ‘हम इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रहे हैं। जांच की जा रही है। हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और सभी विमानन कंपनियों के लिए एक मिसाल कायम करेंगे।’ यात्रियों को आज भी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि इंडिगो ने लगभग 500 उड़ानें रद्द की जो रविवार को रद्द की गई लगभग 650 उड़ानों से कम थीं। इस संकट से पहले इंडिगो हर दिन लगभग 2,300 उड़ान संचालित करती थी।

इंडिगो में यह गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि उसके पास नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त पायलट नहीं थे। ये नियम 1 नवंबर को लागू हुए थे। इंडिगो के एक बोर्ड सदस्य ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि एल्बर्स को हटाने पर विचार किया जाना चाहिए मगर उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा सीईओ तलाशना आसान नहीं है जो रोज़ाना लगभग 2,300 उड़ान संचालित करने वाली विमान कंपनी को संभाल सके। इसलिए कोई भी फैसला बहुत सोच-समझकर लेना होगा।

हालांकि उन्होंने कहा कि अगर सरकार का दबाव बढ़ता है और जुर्माना काफी ज्यादा होता है तो एल्बर्स को जाने के लिए कहा जा सकता है।

बोर्ड के एक अन्य सदस्य ने कहा कि एल्बर्स ने विमानन क्षेत्र में लंबे करियर के दौरान कई संकटों को संभाला है और यह एक और बड़ा संकट है जिससे प्रभावी तरीके से निपटना होगा।

बोर्ड सदस्य ने कहा कि पायलट ड्यूटी रोस्टर का प्रबंध करने और पायलटों की नियुक्ति का जिम्मा देखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बोर्ड के तीसरे सदस्य ने भी नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा कि स्थिति गंभीर हो गई थी लेकिन अब इसमें सुधार हो रहा है।

इस बारे में जानकारी के लिए इंडिगो को ईमेल भेजा गया मगर खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं आया।

■ संबंधित समाचार: पृष्ठ 2

> **इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द किए जाने के संबंध में जांच शुरू कर दी गई है और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि अन्य विमानन कंपनियों के लिए नजीर पेश की जा सके।**
>
> के राममोहन नायडू, नागर विमानन मंत्री

- कंपनी ने डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस के जवाब में कहा कि संचालन में रुकावट का सटीक कारण बताना अभी संभव नहीं
- कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है
- सोमवार को 500 उड़ानें रद्द, रविवार को लगभग 650 उड़ान रद्द हुई थी

सीमा शुल्क के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म

मोनिका यादव
नई दिल्ली, 8 दिसंबर

वित्त वर्ष 2027 के बजट से पहले एक बड़े बदलाव के तहत वित्त मंत्रालय सीमा शुल्क से जुड़ी सभी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की योजना बना रहा है। इसके तहत भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईगेट), जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) और भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस) को एकीकृत कर राष्ट्रीय सीमा शुल्क प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।

भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे के जरिये व्यापारी ई-फाइलिंग और सीमा शुल्क भुगतान करते हैं। इसी तरह आरएमएस जोखिम-आधारित जांच को स्वचालित करता है और आईसीईएस सीमा शुल्क स्थल पर बैकएंड मूल्यांकन और क्लीयरेंस कामकाज को संभालता है। वर्तमान में सीमा शुल्क के तीनों तंत्र अलग-अलग सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं और पूरी तरह से एक-दूसरे से जुड़े नहीं हैं जिससे कागजी कार्रवाई में देरी और दोहराव होता है। इस कदम से कारोबारी सुगमता बढ़ने और देश की वैश्विक व्यापार रैंकिंग में सुधार होने की उम्मीद है। सरकार आगामी बजट वित्त वर्ष 2026-27 में इस परियोजना के लिए धन आवंटित कर सकती है।

सरकारी अधिकारी ने कहा कि मेगा परियोजना के लिए अभिरुचि पत्र जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। (शेष पृष्ठ 4 पर)

डिजिटल प्रक्रिया

- सरकार 2027 तक सीमा शुल्क की समूची प्रक्रिया को डिजिटलीकृत करने की कर रही तैयारी
- इससे कारोबारी सुगमता और पारदर्शिता बढ़ेगी

स्टारलिंक सेवा के लिए हर माह खर्च करने होंगे 8,600 रुपये

गुलवीन औलख
नई दिल्ली, 8 दिसंबर

उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने वाली अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक ने भारत में अपनी सेवाओं के लिए कीमत तय कर दी है। कंपनी रिहायशी परिसरों में अपनी सेवाओं के लिए 8,600 रुपये प्रति माह और आवश्यक उपकरण स्थापित करने के लिए एकमुश्त 34,000 रुपये का शुल्क वसूलेगी। इसके तहत उपयोगकर्ताओं को असीमित डेटा, 99.9 फीसदी अपटाइम अथवा नेटवर्क की सुनिश्चित उपलब्धता और 30 दिनों का ट्रायल पीरियड मिलेगा।

ईलॉन मस्क के नेतृत्व वाली कंपनी ने अभी तक कारोबारी अथवा एंटरप्राइज उपयोगकर्ताओं के लिए कीमतों की घोषणा नहीं की है। मगर कंपनी की वेबसाइट पर बताया गया शुल्क रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, बीएसएनएल और एसीटी सहित मौजूदा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के शुरुआती शुल्कों के मुकाबले करीब दस गुना और औसत ब्रॉडबैंड प्लान के मुकाबले पांच गुना अधिक है।

जानकारों ने बताया कि बांग्लादेश जैसे बाजारों के लिए यह शुल्क काफी अधिक है। वहां मासिक सबस्क्रिप्शन 40 से 50 डॉलर यानी 3,400 से 4,300 रुपये है और उपकरण की कीमत 300 से 400 डॉलर यानी 25,800 से 34,400 रुपये के बीच है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

आज का सवाल

क्या स्टारलिंक की सेवाएं शुरू होने से ब्रॉडबैंड में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा?

www.bshindi.com पर राय भेजें।

आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो Y और यदि न है तो N लिखकर 57007 पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या इंडिगो में व्यवधान लापरवाही का नतीजा है?

हां	नहीं
94 %	6 %

तेलंगाना पर ट्रंप समूह का बड़ा दांव

शाइन जेकब
हैदराबाद, 8 दिसंबर

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के परिवार के नेतृत्व वाले ट्रंप समूह ने आज कहा कि वह अगले 10 वर्षों के दौरान तेलंगाना में करीब 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा। यह अमेरिका के बाहर ट्रंप परिवार के सबसे बड़े निवेश में से एक होगा। इस घोषणा से महज एक दिन पहले राज्य सरकार ने हैदराबाद में एक महत्त्वपूर्ण सड़क का नाम डॉनल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। हैदराबाद में अमेरिका के महावाणिज्य दूतावास के सामने वाली सड़क को अब ‘डॉनल्ड ट्रंप एवेन्यू’ कहा जाएगा।

इस निवेश का दायरा राज्य में रियल एस्टेट एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के अलावा मीरखानपेट के समीप ‘भारत फ्यूचर सिटी’ तक होगा। फ्यूचर सिटी रेवंत रेड्डी सरकार की एक विशाल शहरी परियोजना है जो हैदराबाद से करीब दो घंटे की दूरी पर है। यह 765 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें श्रीशैलम और नागार्जुन सागर राजमार्गों के बीच 56 गांव शामिल हैं। फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफसीडीए) इसका निर्माण कर रही है।

तेलंगाना राइजिंग समिट के दौरान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी (बीच में) ट्रंप मीडिया ऐंड टेक्नॉलजी ग्रुप के निदेशक एरिक स्विडर (दाएं) और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी फोटो: पीटीआई

ट्रंप मीडिया ऐंड टेक्नॉलजी ग्रुप के निदेशक एरिक स्विडर ने भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित तेलंगाना राइजिंग समिट को संबोधित करते हुए कहा, ‘मैं माननीय मुख्यमंत्री (ए रेवंत रेड्डी) को यह बताना चाहता हूं कि अगले 10 वर्षों के दौरान हम अपने संगठनों के जरिये फ्यूचर सिटी और यहां के इलाकों को विकसित करने में 1 लाख करोड़ रुपये तक का निवेश करना चाहते हैं। मैं यह अवसर देने के लिए आभारी हूं।’ उन्होंने कहा, ‘भारत आगे बढ़ता रहेगा और टेक्नॉलजी के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करेगा। मैं समझता हूं यह जरूरी है कि हम मिलकर काम करने और साथ मिलकर निवेश के तरीके तलाशें। हमने यहां ऐसी टेक्नॉलजी देखी है जहां निवेश के लिए मैं काफी उत्साहित हूं।’ ट्रंप परिवार भारत में ट्रंप टावर्स के जरिये अपनी पहचान पहले ही बना चुका है जो ट्रंप ब्रांड की रियल एस्टेट परियोजनाओं की श्रृंखला है। मगर भारत में ट्रंप टावर्स का कारोबारी मॉडल ब्रांड लाइसेंसिंग रणनीति का पालन करता है और उसमें कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं होता है। फिलहाल देश में चार ट्रंप टावर संपत्तियां मुंबई, पुणे, गुरुग्राम और कोलकाता में हैं।

स्विडर ने कहा, ‘मैं समझता हूं कि पूंजी प्रवाह को भी रास्ता मिल जाए तो वह पानी की ही तरह सबसे आसान जगह की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगेगी। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यहां हमारी पूंजी का स्वागत किया जाएगा। यह एक ऐसी जगह है जो तेजी से आगे बढ़ रही है।’

स्विडर ने कहा, ‘अगर आप 20 साल पीछे जाते हैं तो भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कॉल सेंटर तक ही सीमित था। मगर आज आप देख सकते हैं कि दुनिया भर की प्रौद्योगिकी कंपनियों में कौन काम कर रहा है। इससे आप समझ जाएंगे कि प्रतिभा भारत से आ रही है। आज आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में प्रौद्योगिकी पूंजी भारत से आ रही है। भारत आगे बढ़ रहा है।’

फ्यूचर सिटी की एक संभावित परियोजना बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन द्वारा विकसित होने वाली विश्वस्तरीय फिल्म सिटी है। ऐसी खबरें हैं कि रिलायंस फाउंडेशन की वन्यजीव संरक्षण पहल वनतारा भी इस क्षेत्र के समीप पशुओं के लिए एक बचाव एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। शहर में करीब 3,000 करोड़ रुपये की होटल परियोजनाएं भी संभावित हैं।

Insight strengthens with choice.

Choosing to stay informed is choosing to stay ahead.

Business Standard
Insight Out

खबरों में रहे स्टॉक

एचसीएल टेक्नॉलजीज

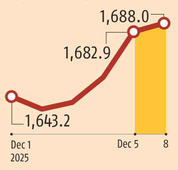

ऊर्जा बचाने वाले चिप निर्माण के लिए डॉल्फिन सेमीकंडक्टर के साथ साझेदारी की
₹ 1,682.9 पिछला बंद भाव
₹ 1,688.0 आज का बंद भाव
0.3 % ▲

टॉरंट पावर

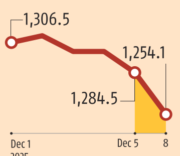

जापान की जेरा के साथ एलएनजी खरीद के लिए 10 वर्षीय करार
₹ 1,284.5 पिछला बंद भाव
₹ 1,254.1 आज का बंद भाव
-2.4 % ▼

ट्रांसरेल लाइटिंग

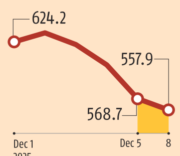

जीसीसी क्षेत्र में टीऐंडडी ईपीसी ठेका समेत 822 करोड़ रु के नए ऑर्डर मिले
₹ 568.7 पिछला बंद भाव
₹ 557.9 आज का बंद भाव
-1.9 % ▼

कॉफोर्ज

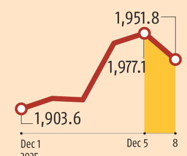

मिशन-क्रिटिकल को आधुनिक बनाने के लिए जेड/टीपीएफ सीओई पेश किया
₹ 1,977.1 पिछला बंद भाव
₹ 1,951.8 आज का बंद भाव
-1.3 % ▼

साइंट

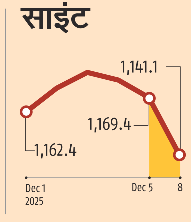

नेविटास सेमीकंडक्टर के साथ रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत
₹ 1,169.4 पिछला बंद भाव
₹ 1,141.1 आज का बंद भाव
-2.4 % ▼

संक्षेप में

केयर्न ऑयल ऐंड गैस की नजर विस्तार पर

वेदांत समूह की सहायक कंपनी केयर्न ऑयल ऐंड गैस ने अगले दो से तीन वर्षों में कंपनी की 5 अरब डॉलर की निवेश योजना के तहत तेल एवं गैस परियोजनाओं में रिग की स्थापना और रिकवरी बढ़ाने के लिए वैश्विक कंपनियों से अभिरुचि पत्र (ईओआई) मांगा है। कंपनी ने बताया कि केयर्न विभिन्न प्रकार के जलाशयों में पुराने संयंत्रों का विस्तार करने के लिए तेल एवं गैस परियोजनाओं में रिकवरी बढ़ाने के वास्ते अनुभवी भागीदारों की तलाश कर रही है। इसमें एल्कलाइन सर्फेक्टेंट पॉलीमर (एएसपी) जैसी उन्नत तेल रिकवरी (ईओआर) तकनीकें और अन्य शामिल हैं। *बीएस*

स्विगी को शेयरधारकों से रकम जुटाने की मंजूरी

स्विगी ने सोमवार को बताया कि उसके शेयरधारकों ने क्यूआईपी के जरिये 10,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी के शेयरधारकों ने चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 26) के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की गई कंपनी की पहली असाधारण आम बैठक में विशेष प्रस्ताव के जरिये रकम जुटाने की मंजूरी दी। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा गया है, 'हम सूचित करना चाहते हैं कि 14 नवंबर, 2025 के नोटिस में उल्लिखित प्रस्ताव को शेयरधारकों ने आवश्यक बहुमत से पारित कर दिया है।' *बीएस*

ट्राई ने नकारा 5 प्रतिशत शुल्क का प्रस्ताव

दूरसंचार नियामक ट्राई ने सोमवार को दूरसंचार विभाग के उस प्रस्ताव को नकार दिया, जिसमें उपग्रह संचार (सैटकॉम) कंपनियों से चार प्रतिशत की जगह पांच प्रतिशत वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क वसूलने की बात कही गई थी। इसमें शहरी क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 500 रुपये का शुल्क हटाने का प्रस्ताव भी था। विभाग ने ट्राई की उन सिफारिशों में बदलाव की मांग की थी। *बीएस*

60 फीसदी घरेलू हवाई मार्गों पर इंडिगो का ही एकछत्र राज

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 8 दिसंबर

इंडिगो अब एकमात्र ऐसी विमानन कंपनी है जो आश्चर्यजनक रूप से देश के 60.4 प्रतिशत घरेलू मार्गों पर अकेले ही परिचालन कर रही है। एक दशक पहले उसके पास सिर्फ 22.3 प्रतिशत घरेलू मार्ग थे। इस तथ्य से यह बात जाहिर होती है कि उसके परिचालन संकट ने देश भर में हवाई यात्रा को क्यों पंगु बना दिया है। विमानन क्षेत्र का विश्लेषण करने वाली फर्म सिरियम की ओर से साझा किए गए 10 वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि जो पहले प्रतिस्पर्धी वितरण था वह कैसे एक ही हाथ में चला गया।

देश के कुछ सबसे व्यस्त मार्गों पर यह दबदबा साफ दिखता है। चेन्नई-कोयंबत्तूर और कोलकाता-हैदराबाद मार्गों पर गौर करें। इन मार्गों पर पिछले महीने कुल मिलाकर 927 निर्धारित उड़ानें (क्रमशः 472 और 455) हुईं या फिर चेन्नई-तिरुचिरापल्ली और अहमदाबाद-हैदराबाद सेक्टर को लें, जिनमें संयुक्त रूप से 688 उड़ानें (क्रमशः 360 और 328) दर्ज की गईं। इन सभी प्रमुख मार्गों पर खास बात यह है कि महीने भर में करीब 1,615 मासिक उड़ानों में से हरेक उड़ान इंडिगो की थी। किसी दूसरी कंपनी की एक भी उड़ान नहीं थी।

10 साल पहले महज 22 प्रतिशत घरेलू मार्गों पर अकेले परिचालन करने वाली इंडिगो अब देश में बड़े वायु मार्ग नेटवर्क पर अपना दबदबा बनाए हुए है

लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। नवंबर 2015 में देश के घरेलू हवाई नेटवर्क में 355 अलग-अलग विशिष्ट मार्ग शामिल थे और इंडिगो उनमें से 79 पर अकेली थी। हालांकि इंडिगो तब भी सबसे बड़ी उड़ान कंपनी थी, लेकिन उसे फिर भी एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी अन्य विमानन कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिनका अपने अपने विशेष क्षेत्रों में दबदबा था। आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2015 में एयर इंडिया 49 मार्गों पर जबकि स्पाइसजेट 41 मार्गों पर अकेली परिचालक थी। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो नवंबर 2015 में भारत में लगभग 22.3 प्रतिशत घरेलू मार्गों पर केवल इंडिगो उड़ान भरती थी, 13.8 प्रतिशत पर केवल एयर इंडिया और 11.5 प्रतिशत पर स्पाइसजेट की उड़ानें थीं।

इसके 10 साल बाद जहां नवंबर 2025 तक अलग-अलग विशिष्ट घरेलू मार्गों की कुल संख्या लगभग तीन गुना बढ़कर 1,004 हो गई, वहीं इंडिगो का खास मार्ग नेटवर्क, जहां वह अकेली सिरमौर है, पिछले महीने तक लगभग आठ गुना बढ़कर 606 मार्गों तक फैल गया। इस भारी असंतुलन से जाहिर होता है कि पिछले 10 वर्षों में घरेलू हवाई बाजार के विस्तार का एक बड़ा हिस्सा एक ही विमानन कंपनी द्वारा किया गया है और हर 10 में से 6 घरेलू मार्ग पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।

स्पाइसजेट और एयर इंडिया के खास क्षेत्र बड़े स्तर पर सिकुड़ चुके हैं। सिरियम के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने एयर इंडिया केवल 6 मार्गों पर और स्पाइसजेट 11 मार्गों पर अकेली परिचालक थी। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो नवंबर 2015 में भारत में लगभग 60.4 प्रतिशत घरेलू मार्गों पर केवल इंडिगो की उड़ानें थीं, 3 प्रतिशत पर केवल एयर इंडिया समूह (जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस भी शामिल है) की और 1.1 प्रतिशत पर केवल स्पाइसजेट की उड़ानें थीं।

इंडिगो से मुआवजे पर विचार कर रहे हवाई अड्डा संचालक

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 8 दिसंबर

पिछले सप्ताह इंडिगो द्वारा लगभग 4,500 उड़ानों को असाधारण रूप से रद्द किए जाने के कारण हुए राजस्व नुकसान का आकलन कर रहे निजी हवाई अड्डा संचालक विमानन कंपनी से मुआवजा मांगने पर आंतरिक रूप से विचार-विमर्श कर रहे हैं।

नाम न छापने की शर्त पर बड़ी निजी हवाई अड्डा संचालक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हां, हम कारोबार में हुए नुकसान के लिए मुआवजे पर विचार करने के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधन के बीच चर्चा कर रहे हैं। हमारा आपसी संबंध है और यह संवेदनशील मामला है। संकट को खत्म होने दें और उड़ान संचालन स्थिर हो जाए, उसके बाद हम अंतिम फैसला लेंगे। हमें पूरी तस्वीर तभी मिलेगी, जब सभी उड़ानें वापस आ जाएंगी, जिसमें कुछ दिन लग सकते हैं।'

हवाई अड्डों के विमानन संबंधी राजस्व का बड़ा हिस्सा विमानों के उड़ने से आता है, भले ही गैर-विमानन राजस्व (खुदरा आय, ड्यूटी फ्री, लाउंज सेवाएं आदि) बढ़ने के साथ इसकी हिस्सेदारी कम हो रही है। इनमें लैंडिंग और पार्किंग शुल्क शामिल हैं, जिनका बिल सीधे विमानन कंपनियों को देना होता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में विमानन कंपनियों द्वारा इसका बोझ आंशिक या पूर्ण रूप से यात्रियों पर डाल दिया जाता है और इसे टिकट की कीमतों में शामिल किया जाता है क्योंकि वे विमानन कंपनियों की परिचालन लागत का हिस्सा बन जाते हैं।

हवाई अड्डे यात्रियों से सीधे यात्री सेवा शुल्क भी लेते हैं, जिसका उपयोग हवाई अड्डे की सुरक्षा, सुविधा और अन्य सेवाओं के लिए किया जाता है। कुछ हवाई अड्डों पर यात्रियों से उपयोगकर्ता विकास शुल्क भी लिया जाता है, जिसका उपयोग हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए किया जाता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु और हैदराबाद जैसे देश के प्रमुख हवाई अड्डे बड़े स्तर पर उड़ानों के रद्द होने के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

स्टारलिंक की सेवा 8,600 रु ...

पृष्ठ 1 का शेष

मगर स्टारलिंक का प्लान श्रीलंका के मुकाबले सस्ता है। स्टारलिंक की वेबसाइट के अनुसार, श्रीलंका में मासिक सबस्क्रिप्शन 100 से 125 डॉलर यानी 8,600 से 10,750 रुपये है और उपकरण की कीमत 900 से 1,000 डॉलर यानी 77,400 से 86,000 रुपये के बीच है। डाउनलोड स्पीड 190 से 360 एमबीपीएस के बीच है।

विशेषज्ञों ने कहा कि भारत के लिए बताई गई कीमतों पर स्टारलिंक यहां रिलायंस जियो और भारती एयरटेल की ब्रॉडबैंड सेवाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी। यहां अधिकतम शुल्क 2,500 रुपये से 3,500 रुपये तक हो सकता है, मगर उसमें आईपीटीवी और ओटीटी स्ट्रीमिंग ऐप के प्लान भी शामिल होंगे।

रेटिंग एजेंसी इक्रा के उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख अंकित जैन ने कहा, 'स्टारलिंक द्वारा घोषित प्लान फाइबर या कॉपर पर दी जा रही वायर्ड कनेक्शन के मुकाबले काफी अधिक है। भारत जैसे कीमत के प्रति संवेदनशील बाजार में इस तरह के प्लान को शायद ही कोई स्वीकार करेगा।' एक वैश्विक सलाहकार फर्म के क्षेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि प्रतिस्पर्धा का प्रभाव संभवतः आम लोगों के बाजार में महसूस नहीं किया जाएगा। यह सेवा दूरदराज के इलाकों और खनन, ऊर्जा, समुद्री एवं रक्षा जैसे एंटरप्राइज श्रेणी के उपयोग मामलों में तेजी लाएगी। इस उद्योग पर नजर रखने वाले एक अन्य व्यक्ति ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि ग्राहकों की भुगतान करने की प्रवृत्ति ही कीमत तय करेगी। उन्होंने कहा, 'अगर बाजार इस शुल्क को स्वीकार करता है तो इससे होम ब्रॉडबैंड के टैरिफ में उम्मीद से ज्यादा तेज वृद्धि हो सकती है।'

मस्क ने 30 नवंबर को जिरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामत से बातचीत में कहा था कि स्टारलिंक मौजूदा दूरसंचार कंपनियों के लिए पूरक होगी क्योंकि पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद उपग्रहों के उसके नेटवर्क के लिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सेवा देना संभव नहीं है। इससे ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों को अधिक लाभ होगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटेल ने भारतीय बाजार के लिए इंटेल के उत्पादों के विनिर्माण और पैकेजिंग की संभावना तलाशने के लिए समझौता किया है। दोनों कंपनियों ने यह जानकारी दी है। *बीएस*

न्यायालय ने इंडिगो मामले में दखल से किया इनकार

भाविनी मिश्रा
नई दिल्ली, 8 दिसंबर

सर्वोच्च न्यायालय ने इंडिगो के बड़े स्तर पर उड़ानें रद्द करने के मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया और कहा कि केंद्र सरकार पहले से ही इस मसले से निपटने के लिए कदम उठा रही है। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि उसे पता है कि उड़ानों के रद्द होने से व्यापक व्यवधान हुआ है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा, 'यह वास्तव में गंभीर मामला है। देशभर में लाखों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। हमें पता है कि सरकार ने इस स्थिति का संज्ञान लिया है और इस पर कार्रवाई कर रही है। कई यात्रियों को स्वास्थ्य या व्यक्तिगत जरूरी काम हो सकते हैं।' एक वकील ने अदालत के सामने इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यात्रियों को संतोषजनक सूचना दिए बिना उड़ानें रद्द की जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि लगभग 2,500 उड़ानों में देर हुईं, जिससे देश भर के लगभग 95 हवाई अड्डों पर यात्रियों को परेशानी हुई।

इंडिगो को उठाना पड़ सकता है वित्तीय नुकसान : मूडीज

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ानों में व्यापक स्तर पर हुई अव्यवस्था राजस्व हानि के साथ ही उड़ानों के रद्द होने पर संभावित जुर्मानों की वजह से वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है। मूडीज रेटिंग्स ने सोमवार को यह बात कही।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि एयरलाइन एक साल से अधिक पहले विमानन उद्योग के लिए निर्धारित नियमों के लिए सही योजना नहीं बना पाई, जिसके चलते उसे इस विफलता का सामना करना पड़ा। मूडीज ने टिप्पणी में कहा कि ये अव्यवस्थाएं एयरलाइन की साख के लिए भी नकारात्मक हैं। इसमें कहा गया, 'अस्थायी राहत के बावजूद नए विमानन नियमों के लिए प्रभावी योजना न बना पाना एयरलाइन की साख के लिए नकारात्मक है।' यह अव्यवस्था बेहद व्यस्त शीतकालीन उड़ान सत्र की वजह से और बिगड़ गई। इस बार उड़ानें रद्द होने का सिलसिला दो दिसंबर से शुरू हुआ और एयरलाइन ने 5 दिसंबर को 1,600 से अधिक उड़ानों को रद्द किया। एयरलाइन अभी तक सामान्य स्थिति बहाल नहीं कर पाई है।

सोमवार को भी 500 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं। मूडीज ने कहा, 'ये व्यवधान साख के लिए नकारात्मक हैं, क्योंकि इंडिगो को राजस्व हानि, उड़ान रद्दीकरण, रिफंड और प्रभावित यात्रियों को अन्य क्षतिपूर्ति के साथ ही डीजीसीए द्वारा लगाए जा सकने वाले जुर्मानों के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।' *भाषा*

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of india Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)
स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

पंजीकृत कार्यालय : आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110 019
फोन : 41732000 फैक्स: 011–26230201
वेबसाईट : www.ifciltd.com
सीआईएन : L74899DL1993GOI053677

निविदा संख्याः आईएफसीआई/एचओ/सीएमएल & आर/08/2025 - 26, दिनांक 09/12/2025
आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा स्विस चैलेंज मेथड के तहत वित्तीय परिसम्पतियों की बिक्री

आईएफसीआई लिमिटेड अपने वित्तीय परिसम्पतिया, जो रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को कॉर्पोरेट लोन है, की बिक्री (असाइनमेंट के ज़रिए) के लिए बोलियां आमंत्रित करता हैः

(करोड़ रुपये में)

बकाया राशि (15/11/2025 तक)	आरक्षित मूल्य	बिक्री की शर्तें
37.17*	55.00	100% नकद आधार पर

*इसमें बकाया राशि के अलावा, बिना लगाया गया ब्याज और पेनल्टी/दूसरे प्रभार वगैरह शामिल नहीं हैं।

यह नीलामी ऊपर दिए गए रिज़र्व प्राइस के आधार पर "स्विस चैलेंज मेथड" के तहत हो रही है।

निविदा दस्तावेज़ तथा विस्तृत निबंधन व शर्तें हमारी वेबसाइट **(https://www.ifciltd.com) निविदाओं →संपत्तियों की बिक्री→एनपीए** के तहत अपलोड कर दिया गया है। ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 16/12/2025 सांय 5:00 बजे तक है। ई–नीलामी 02/01/2026 तारीख को होगी।

निविदा से सम्बन्धित सभी शुद्धि–पत्र/परिशिष्ट/आशोधन/समय वृद्धि की सूचना/स्पष्टीकरण आदि, यदि कोई हो, को केवल **(https://www.ifciltd.com)** वेबसाइट पर ही डाला जाएगा।

नोट: आईएफसीआई के पास सभी अथवा किसी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए, चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, पूर्णतः अथवा अंशतः अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 09/12/2025
हस्ताक्षर/–
उप महाप्रबन्धक (सीएमएल एंड आर)

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
आगरा शाखा – ऑफिस नंबर 504, 5वीं मंजिल पर, बिजनेस स्क्वायर, ब्लॉक-ई-15/8, संजय प्लेस, आगरा - 282002 (उ.प्र.)
मुरादाबाद शाखा – शॉप नंबर - 6, प्रथम मंजिल, मित्तल कॉम्प्लेक्स, स्प्रिंग फील्ड के सामने, दिल्ली रोड, मुरादाबाद - 244001 (उ. प्र.)

ई–नीलामी – बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/ जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1	(लोन कोड नं. 01410000922/ आगरा शाखा) अंकुश (ऋणी) मिथलेश (सह-ऋणी)	10-07-2025 & ₹ 9,10,050/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नं. 216 पर मकान, मौजा प्रेमपुर रायपुरा लाईपार (संपत्ति क्षेत्रफल 65.1 वर्गमीटर) फीरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 283203, **चर्तुसीमाएँ:–** पूर्व- 12 फीट चौड़ा रोड़, पश्चिम- विक्रेता की संपत्ति, उत्तर- कौशल किशोर का प्लाट, दक्षिण- 12 फीट चौड़ा रोड़	₹ 11,59,760/-	₹ 1,15,976/-	भौतिक
2	(लोन कोड नं. 05400000349 एवं 05400000595/ मुरादाबाद शाखा) राजकुमार (ऋणी) ओम प्रकाश (सह-ऋणी)	07-07-2025 & ₹ 8,57,996/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नं. 162-मिन पर मकान, ग्राम अजीतपुर (संपत्ति का क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर), रामपुर, उत्तर प्रदेश- 244901 **चर्तुसीमाएँ:–** पूर्व- 10 फीट चौड़ा रोड़ पश्चिम - अन्य का प्लाट, उत्तर- सुशील का प्लाट, दक्षिण- राजकिशोर शर्मा का प्लाट	₹ 14,62,400/-	₹ 1,46,240/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **12-01-2026 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **13-01-2026 दोपहर 03.00 बजे से 04.00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है।
3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी।
4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/ signup**, लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **राकेश तिवारी (संपर्क नंबर 9570443300) एवं उदयवीर सिंह (संपर्क नंबर 9997306900)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई–मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com**, फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है।
8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।
9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/–** है।
10. यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान : उत्तरप्रदेश, दिनांक : 09-12-2025
सही/– प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 20 प्रतिशत बढ़ी

शाइन जेकब
हैदराबाद, 8 दिसंबर

त्योहारी सीजन के बाद भी ग्राहकों की लगातार दिलचस्पी के कारण नवंबर के दौरान देश में यात्री वाहनों की खुदरा ब्रिकी में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (फाडा) ने आज यह जानकारी दी। फाडा के अध्यक्ष सीएस विघ्नेश्वर ने कहा कि बिना बिके वाहनों का स्टॉक तेजी से घटकर 44 से 46 दिन रह गया। पहले यह 53 से 55 दिन का था। यह मांग-आपूर्ति के बेहतर संतुलन को दर्शाता है। इस वजह से नवंबर में बिक्री बढ़कर 3,94,152 वाहन हो गई, जबकि एक साल पहले यह 3,29,253 वाहन थी।

उन्होंने कहा कि जीएसटी के फायदों के अलावा शादियों के सीजन, ज्यादा इंतजार वाले मॉडलों की बेहतर आपूर्ति और कॉम्पैक्ट स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों के लगातार जोर से भी बिक्री में उछाल को मदद मिली।

दूसरी तरफ नवंबर में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 3 प्रतिशत की गिरावट आई। साथ ही निर्माण उपकरणों की बिक्री में भी इस महीने 17 प्रतिशत की गिरावट आई। अलबत्ता समीक्षाधीन महीने के दौरान वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 20 प्रतिशत, तिपहिया वाहनों में 24 प्रतिशत और ट्रैक्टरों में 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। त्योहारों के बाद का महीना होने के बावजूद इसी कारण से नवंबर में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 2 प्रतिशत बढ़कर 33 लाख पहुंच गई।

विघ्नेश्वर ने कहा, 'नवंबर 2025 में त्योहार बाद की सामान्य सुस्ती का खास असर नहीं हुआ। बिक्री ने असामान्य रूप से अधिक तुलनात्मक आधार के बावजूद जोरदार प्रदर्शन किया। सामान्य तौर पर त्योहारों के बाद वाले महीने में वाहनों की खुदरा बिक्री में नरमी आती है। हालांकि इस साल त्योहारी सीजन के ज्यादातर पंजीकरण अक्टूबर 2025 में ही पूरे कर लिए गए थे।'

ईवी की गति धीमी, पेट्रोल गाड़ियों का फर्राटा

सोहिनी दास
मुंबई, 8 दिसंबर

इस साल नवंबर में यात्री वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। इक्विरस सिक्योरिटीज और फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के आंकड़ों से इसका पता चलता है। जीएसटी 2.0 यानी कर दरों में कटौती से कीमतें घटने और पेट्रोल गाड़ियों के प्रति उपभोक्ताओं की पसंद में पक्के बदलाव का असर हुआ और इलेक्ट्रिक वाहनों की पैठ में नरमी आई।

इक्विरस ने अपने हालिया ईंधन के हिसाब से बताए मासिक खुदरा ट्रैकर में कहा है कि नवंबर में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री एक साल पहले के मुकाबले करीब 20 फीसदी बढ़ी है। इसे किफायती होने, बढ़िया मॉडलों की मौजूदगी और त्योहारी सीजन की बची हुई मांग से बल मिला है, जो पहले आपूर्ति संबंधी समस्याओं के कारण आंशिक तौर पर तंग थी।

मगर इलेक्ट्रिक कारों की पैठ 3.7 फीसदी रही जो माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती पहले करीब 5 फीसदी के स्तर पर थी। इससे पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों की ओर मांग के झुकाव का पता चलता है।

यह रुझान खासतौर पर लग्जरी कारों की श्रेणी में दिख रहा है। पिछले साल यानी 2024 के मुकाबले 2025 में लग्जरी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच ज्यादा होने के बावजूद मर्सिडीज बेंज इंडिया ने कहा कि जीएसटी 2.0 के बाद सितंबर-नवंबर की अवधि में कुल मिलाकर उद्योग में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन 16 से घटकर 12 फीसदी रह गए हैं। यह गिरावट इन तीन महीनों में भी जारी रही है, जिससे यह साफ होता है कि कर कटौती ने खरीदारों को पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की ओर मोड़ दिया है।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी संतोष अय्यर ने कहा कि जीएसटी में बदलाव के बाद से ब्रांड ने ग्राहकों की पसंद में संरचनात्मक बदलाव देखा है। अय्यर ने कहा, 'लक्जरी उद्योग में कुल बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की पैठ कम होने के बावजूद जीएसटी 2.0 की घोषणाओं के बाद मर्सिडीज-बेंज ने पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों की ओर लगातार रुझान देखा है।'

दिल्ली संस्करण : बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा नीतेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जागरण प्रकाशन लिमिटेड, डी–210–211, सेक्टर–63 नोएडा–201301 उ.प्र. और पृथ्वीस दास, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड 10, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर – 302015 से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. DELHIN/2008/27804 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन – 011–23720202/23762742
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई–400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं